

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2875
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

हरित गलियारे

2875. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरों में जैव-विविधता के संरक्षण और उसके सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का संवर्धन करने के लिए हरित गलियारे स्थापित करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे हरित गलियारे वाले शहरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 ([https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I\(2\).pdf](https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)) जारी किए हैं। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 का अध्याय-5 "शहरी नियोजन दृष्टिकोण" हरित शहर से संबंधित है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को क्रियान्वित कर रहा है। मिशन का एक मुख्य उद्देश्य पैदल यात्री पथ, गैर-मोटर चालित और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का निर्माण है। अमृत के तहत, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 323 ग्रीन मोबिलिटी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

इसके अलावा, अमृत के तहत 5,044.28 करोड़ रुपये की लागत से 2,429 पार्क परियोजनाओं का विकास किया गया है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। अमृत 2.0 के तहत अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1,027.62 करोड़ रुपये की लागत की 1,729 पार्क परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

स्मार्ट सिटीज मिशन के एक उप-घटक, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) 1.0 कार्यक्रम के तहत, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में एक ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर विकसित किया जा चुका है। इस परियोजना के लिए हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 115.68 करोड़ रु. का अनुदान दिया जा चुका है। यह परियोजना शहर में 9.25 किलोमीटर लंबे जल निकासी चैनल उंकल नाला के पुनरुद्धार पर केंद्रित है, ताकि यह महज नाला न रहकर समुदाय के लिए एक सर्वांगीण विकसित स्थान बन सके। इस कॉरिडोर के विकास से ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को उंकल नाला से गुजरने वाली शहर की प्रमुख सड़कों से जोड़ने का अवसर मिला है, जिससे शहर में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) कॉरिडोर का एक नेटवर्क तैयार होगा।

"हरित गलियारे" के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 2875 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-1

ग्रीन मोबिलिटी परियोजनाओं की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण परियोजनाएं	कार्यान्वयन चरण में परियोजनाएं	कुल
1	गोवा	7	-	7
2	गुजरात	60	1	61
3	हिमाचल प्रदेश	15	2	17
4	जम्मू और कश्मीर	16	1	17
5	कर्नाटक	41	2	43
6	केरल	109	19	128
7	लद्दाख	1	2	3
8	मध्य प्रदेश	19	2	21
9	मिजोरम	3	-	3
10	नागालैंड	5	-	5
11	सिक्किम	45	-	45
12	पश्चिम बंगाल	2	-	2
कुल		323	29	352

"हरित गलियारे" के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 2875 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- 11

अमृत के अंतर्गत हरित क्षेत्र विकास की राज्य-वार प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	कार्यान्वयन चरण में परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3		3
2	आंध्र प्रदेश	89	10	99
3	अरुणाचल प्रदेश	2		2
4	असम	12	1	13
5	बिहार	25		25
6	चंडीगढ़	3		3
7	छत्तीसगढ़	191	3	194
8	दादरा और नगर हवेली	1		1
	दमन और दीव	1		1
9	दिल्ली	5	2	7
10	गोवा	2		2
11	गुजरात	124		124
12	हरियाणा	33		33
13	हिमाचल प्रदेश	9		9
14	जम्मू और कश्मीर	14		14
15	झारखंड	35		35
16	कर्नाटक	179	2	181
17	केरल	73	5	78
18	लद्दाख	6		6
19	लक्षद्वीप	3		3
20	मध्य प्रदेश	108	3	111
21	महाराष्ट्र	128		128
22	मणिपुर	1	2	3
23	मेघालय	8		8
24	मिजोरम	4		4
25	नागालैंड	10		10
26	ओडिशा	48		48
27	पुदुचेरी	9		9
28	पंजाब	32	11	43
29	राजस्थान	73	4	77
30	सिक्किम	3		3
31	तमिलनाडु	409		409
32	तेलंगाना	35		35
33	त्रिपुरा	3		3
34	उत्तर प्रदेश	297	44	341
35	उत्तराखंड	42	2	44
36	पश्चिम बंगाल	409	6	415
कुल		2429	95	2524

"हरित गलियारे" के संबंध में दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु अतारंकित प्रश्न संख्या 2875 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- III

अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित पार्क परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1	अरुणाचल प्रदेश	8	3.43
2	बिहार	18	41.41
3	दिल्ली	9	24.31
4	गोवा	1	1.83
5	गुजरात	133	120.34
6	हिमाचल प्रदेश	11	2.80
7	झारखंड	25	30.20
8	कर्नाटक	254	142.21
9	केरल	73	40.72
10	मध्य प्रदेश	390	129.77
11	महाराष्ट्र	27	202.08
12	मणिपुर	2	5.36
13	मिजोरम	73	0.75
14	नागालैंड	38	13.06
15	पंजाब	15	10.79
16	राजस्थान	2	2.76
17	सिक्किम	2	0.79
18	तमिलनाडु	565	113.65
19	उत्तर प्रदेश	15	108.21
20	पश्चिम बंगाल	68	33.15
कुल		1729	1027.62
